Revenue Canada, which is a part of the agreement between the Government of India and the Canadian International Development agency (CIDA). A detailed training material has been develped and comprehensive training is being imparted to the officers by the National Academy of Customs, Excise & Narcotics as well as Institute of Cost & Works Accounts of India.

Separate Liaison Officer for OBCs in GIC

1751. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whetehr the General Inssurance Corporation of India and its subsidiaries have been advised to implement Ministry of Personnel O.M. No. 42011/18/96-Estt. (Res.) dated the 6th March, 1997 for appointment of separate Liaison Officer for OBCs;

(b) if so, whether the orders have been uniformally implemented in G.I.C. and its subsidiaries; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. Exclusive Liaison Officers for OBCs have been appointed in four subsidiaries. however in GIC since the total number is small, the same Liaision Officer looks after SCST and OBC.

(c) Does not arise.

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अशोध्य ऋण लेखे

1752. **श्री कपिल सिब्बल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 6171.86 करोड़ रू० अशोध्य ऋण खाते में डाल दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(ग) किस-किस बैंक द्वारा कितनी-कितनी राशि अशोध्य ऋण खाते में डाली गयी है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कोई भी ऋण अशोध्य ऋण खातों में डालने के निर्देश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वे निर्देश क्या हैं?

वित्त मंत्रालय बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) से (ग) संभवतः यह संदर्भ सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों से संबंधित है। वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि देयराशियों की वसूली के लिए सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए और यदि ऋण की वसूली की आगे संभावना न हो तो बैंक के बेहतर हित में बट्टे खाते डालने का निर्णय लिया जा सकता है। निर्णय लेने में गति लाने की दृष्टि से अलग-अलग बैंकों के निदेशक मंडलों ने निर्धारित सुरक्षा/शर्तों और विभिन्न कार्यकर्ताओं को सूचित करने की प्रणाली के अध्ययधीन अशोध्य ऋणों/हानियों को बट्टे खाते डालने की उपयुक्त शक्तियां प्रत्यायोजित की है।

विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण

(राशि करोड़ में)

क्रम सं०	बैंक का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
(क)	स्टेट बैंक समूह			
1.	भारतीय स्टेट बैंक	363.72	398.69	293.67
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	39.25	24.98	26.45

क्रम सं॰	बैंक का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	27.89	15.85	136.69
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	32.93	6.04	26.02
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	50.61	5.72	12.09
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	19.74	4.93	19.62
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	18.95	4.02	2.38
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	4.17	28.96	36.29
(ख)	राष्ट्रीयकृत बैंक			
9.	इलाहाबाद बैंक	55.73	6.71	21.39
10	आन्ध्रा बैंक	38.78	1.95	37.42
11.	बैंक आफ बड़ौदा	270.27	46.42	70.17
12.	बैंक आफ इंडिया	260.38	307.08	217.15
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	81.12	56.52	47.30
14.	केनरा बैंक	200.00	169.49	18.20
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	144.12	138.44	156.83
16.	कारपोरेशन बैंक	18.64	19.13	0.94
17.	देना बैंक	27.34	51.92	58.76
18.	इंडियन बैंक	42.51	115.94	70.28
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5.94	75.01	375.73
20.	ओरियटल बैंक आफ कामर्स	2.13	0.82	46.22
21.	पंजाब नेशनल बैंक	220.77	53.14	150.34
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1.70	2.86	9.93
23.	सिंडिकेट बैंक	24.84	8.03	58.79
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	27.86	38.81	30.57
25.	यूको बैंक	165.07	110.98	220.57
26.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	119.00	96.51	65.48
27.	विजया बैंक	4.19	13.26	12.72
	कुल	2267.65	1742.21	2162.00

Issue of foreign currency dominated bonds by UTI

1753. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the decision taken on the proposed scheme for issue of foreign currency denominated bonds by the UTI, to mop up foreign funds from Indians abroad, indicating the details of the bonds; and

(b) the amount of foreign exchange in various currencies expected by way of sale of bonds and the amount actually collected through these bonds?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) In the current year's Budget it was announced that UTI would launch a new India Millennium Scheme which will be open for subscription only for NRIs. The scheme would invest in shares of Indian companies with high potential for growth and high quality Indian debt. The scheme is yet to be launched